

प्रेषक,

जे०पी० जोशी  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २० अक्टूबर, 2015

**विषय:-** डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट, देहरादून को ग्राम कोटड़ा सन्तोर एवं झाझरा, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून के विभिन्न खाता/खसरा संख्याओं के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कुल 2.8442 है० (7.025 एकड़) अतिरिक्त भूमि क़य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी, डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट, देहरादून के पत्र संख्या-जे.एन.एस.सी.टी./2015/06/850, दिनांक 15.6.2015 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त लिये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3164/XVIII(II)/2013-1(04)/2012, दिनांक 27.09.2013 एवं शासनादेश संख्या-1192/XVIII(II)/2013-1(04)/2012, दिनांक 15.05.2014 द्वारा उक्त ट्रस्ट को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रदत्त कुल 20 एकड़ भूमि क़य की अनुमति के क्रम में श्री राज्यपाल, डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट, देहरादून को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम कोटड़ा सन्तोर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून के खाता संख्या-13, 15, 58, 113, 129, 238 एवं 376 में क्रमशः खसरा संख्या-345 रकबा 0.0400 है०, खसरा संख्या-382 रकबा 0.0790 है०, खसरा संख्या-368 रकबा 0.2272 है०, खसरा संख्या-368 रकबा 0.0530 है०, खसरा संख्या-388 रकबा 0.0610 है०, खसरा संख्या-345 रकबा 0.0400 है०, खसरा संख्या-387 रकबा 0.0800 है०, खसरा संख्या-388 रकबा 0.03770 है०, खसरा संख्या-66, 72, 73, 74 कुल रकबा 0.6140 है० (क्रमशः 0.0800, 0.3770, 0.0360, 0.0040, 0.1130 व 0.0040 है०), खाता संख्या-64, 80, 130 व 375 के अन्तर्गत विभिन्न खसरा नम्बरानों की (सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध 02 पृथक-पृथक विक्रय अनुबन्ध पत्र-बिना कब्जा में अंकित विवरणानुसार) की कुल रकबा 1.4200 है० तथा ग्राम झाझरा, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में खाता संख्या-269 के खसरा संख्या-1019, 1020 व 1022 कुल रकबा 0.3100 है० (क्रमशः 0.1100, 0.0500 व 0.1500 है०) अर्थात् कुल 2.8442 है० (7.025 एकड़) अतिरिक्त भूमि क़य की अनुमति, उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-154(2) तथा उत्तराखण्ड (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दि० 15.01.2004 की धारा-154(4)(3)(क)(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क़य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता द्वारा क़य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (निजी विश्वविद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क़य किया गया था उससे



- भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होगा।
- 3- सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा जंगल, कब्रिस्तान, नदी आदि की भूमियों को चिन्हित/समुचित सीमांकन कर अलग रखा जायेगा व इसका अन्तरण या कब्जा न हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाये। केवल संक्रमणीय भूमिधरी (वर्ग-1 क) की अविवादित एवं भार रहित भूमि क्रय की अनुमति अनुमन्य होगी।
  - 4- यदि ट्रस्ट से सम्बन्धित मा० न्यायालय में विचाराधीनवादों में कोई प्रतिकूल निर्णय इस क्रय अनुमति से सम्बन्धित भूमि पर होता है, तो इस पर तदनुसार निर्णय लिया जायेगा।
  - 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
  - 6- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
  - 7- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।
  - 8- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
  - 9- संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्य हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
  - 10- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
  - 11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
  - 12- ट्रस्ट द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु वांछित समस्त अवस्थापना सुविधायें अपने स्तर से उपलब्ध करानी होंगी इसके सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताओं पर ही मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी तथा इस हेतु सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति प्राप्त होने पर ही स्थल पर निर्माण कार्य किया जायेगा।
  - 13- आवेदक द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आवास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
  - 14- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।
  - 15- संस्था द्वारा संगत अधिनियम की धारा 154(4)(3)(2)(क)(1) के अन्तर्गत राज्य के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



- 16- सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा कय हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य अथवा मिलान पर राजकीय भूमि के होने के स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांच कराकर उचित कार्यवाही की जायेगी।
- 17- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 18- सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन से पूर्व सम्बन्धित विभागों से मान्यता/अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 19- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

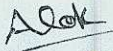
(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव।

पृ०सं०: 1673/XVIII(II)/2015-1(04)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी, डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 15.6.2015 के क्रम में।
- ✓ 5- निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(आलोक कुमार सिंह)  
अनु सचिव।